



मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति, परम पूज्य तुलछराम महाराज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भेंट कर उनका स्नेहाशीष प्राप्त किया।

कांग्रेस में जातिगत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जातियों की पहचान को लेकर विवाद हो सकते हैं।

कुछ कांग्रेस नेताओं को यह भी चिंता है कि यह प्रक्रिया बँटने वाली तथा जटिल हो सकती है तथा इसमें गलतियों की काफी संभावनाएँ हैं। कुल मिलाकर, यह समाज में नए तनाव पैदा कर सकती है।

भारत में आखिरी बार जातिगत आंकड़े 1931 में एकत्रित किए गए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) करवाई थी, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए, क्योंकि इनमें विसंगतियाँ बताई गई थीं। किन्तु आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस उस समय राजनीतिक जोखिम से बचना चाहती थी, क्योंकि वे आंकड़े आरक्षण नीति और सामाजिक समीकरणों को बदल सकते थे।

हालिया वर्षों में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना का समर्थन खुलकर करना शुरू इसलिये किया है, क्योंकि वे सामाजिक न्याय और संसाधनों के पुनर्वितरण पर जोर देना चाहते हैं।

लेकिन पार्टी के भीतर विरोध की प्रमुख वजहें हैं जैसे, राजनीतिक समीकरण, जातिगत ध्रुवीकरण का डर, पारंपरिक वोट बैंक के दूर छिटक जाने की चिंता, इस मुद्दे पर ऐतिहासिक अनिर्णय।

विशेष रूप से भाजपा की ओबीसी वर्ग में बढ़ती पहुंच और क्षेत्रीय सहयोगी दलों के दबाव के मद्देनजर, कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अपना रुख अधिक स्पष्ट करती दिख रही है।

राजस्थान का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुल 23 लाख 33 हजार 162 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और 13 लाख 15 हजार 853 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

इस वर्ष अनारक्षित श्रेणी के 689366, अनुसूचित जाति के 333646, अनुसूचित जनजाति के 150224, अन्य पिछड़ा वर्ग के 948507, इंडक्लूप के 154326 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 11 उभयलिंगी (थर्ड जेंडर) शामिल हुए।

इज़रायल-ईरान युद्ध से खाड़ी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ – के इशारों पर चलने के मामले में इज़रायल का व्यवहार पाकिस्तान से अलग नहीं है। वह एक रणनीतिक कठपुतली बन गया है और उसकी एकरूपा कार्रवाहियाँ पूरे मध्य पूर्व को खतरे में डाल रही हैं। प्रो. पाशा ने यह भी कहा कि भारत सरकार को इस संकट के समय आगे आकर अपने इज़राइल और ईरान दोनों के साथ वर्षों पुराने संबंधों का उपयोग कर विवाद के कूटनीतिक समाधान की दिशा में पहल करनी चाहिए।

भारत, जिसने अब तक दोनों देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित रूप से बनाए रखा है, अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। नई दिल्ली जहां एक ओर इज़राइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी साझेदारी रखता है, वहीं ईरान के साथ उसके सांस्कृतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध भी गहरे हैं। वर्षों से भारत ने ईरान में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे चावहार बंदरगाह, में निवेश किया है, जो उसकी

कोमा में गया कर्मचारी सेवानिवृत्ति तक नियमित वेतन का अधिकारी

जयपुर, 14 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कर्मचारी के कोमा में जाने पर उसे सेवानिवृत्ति तक नियमित वेतन का अधिकारी माना है। अदालत ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कहा है कि वह मेडिकल टीम के जरिए कर्मचारी की दिव्यांगता की जांच दो सप्ताह में पूरी करे तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 20 के तहत निर्णय ले। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश कर्मचारी लक्ष्मण सेन की पत्नी गुडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति जेजीवीएनएल में तकनीकी सहायक हैं। एक दुर्घटना में घायल होकर वे कोमा में चले गए। इसके बाद बिजली कंपनी ने उनका वेतन बंद कर दिया, जबकि दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी दिव्यांग हो जाए तो उसे उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र तक

इसके जवाब में बिजली कंपनी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति की ओर से दिव्यांगता की लेकर कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। ऐसे में उन्हें नियमित वेतन का लाभ नहीं दिया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बिजली कंपनी को दो सप्ताह में याचिकाकर्ता के पति की मेडिकल जांच कर रिपोर्ट के आधार पर धारा 20 के तहत आगामी कार्रवाई करने को कहा है।

नयी दिल्ली, 14 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 से 18 जून के बीच कैनडा, साइप्रस और क्रोएशिया की यात्रा पर जाएंगे और कैनडा में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि मोदी पहले चरण में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस के निमंत्रण पर 15-16 जून, 2025 को वहां की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। दो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की यह पहली यात्रा होगी। मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर जी-7 शिखर सम्मेलन

में भाग लेने के लिए जून 16-17 को कनाडा के कनाईस्कस की यात्रा करेंगे। जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की यह लगातार छठी भागीदारी होगी। शिखर सम्मेलन में

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा आई.रौड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायवा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेरा। फोन: 2200660, फैक्स : 0154-2410146, अजमेर कार्यालय: राधदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेरा। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर।फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी 1-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

ईरान ने की जवाबी कार्यवाही , तेल अवीव के कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया

इज़रायल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी, मिसाइलें दागना बंद नहीं किया तो “तेहरान जलेगा”

तड़के किए गए जवाबी हमलों से पहले, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई ने टेलिविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए जायनिस्ट शासन को “कड़ी सजा” देने की बात कही थी।

इज़राइल के रक्षा मंत्री इम्म्राइल कात्ज़ है, जो दुनिया को वैश्विक युद्ध की ओर धकेल सकता है। इज़राइल का यह दावा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के कगार पर है, निराधार प्रतीत होता है, जैसा कि अमेरिका ने इराक के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, जो अंततः पूरी तरह गलत साबित हुआ।

विशेषज्ञों ने कहा, इसी रणनीति को दोहराते हुए, ट्रम्प प्रशासन के समर्थन से इज़राइल मीडिया में जोर-शोर से ऐसा प्रचार कर रहा है, ताकि ईरान पर हमलों को उचित ठहराया जा सके, तेहरान ने लगातार यह कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह किसी भी तरह के परमाणु हथियार कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

ईरान के शुक्रवार रात और शनिवार

दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है, रणनीतिक विशेषज्ञों ने कहा, यह स्थिति दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर ले जा सकती है।

ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस को चेतावनी दी, अगर उन्होंने इज़रायल की मदद की तो ईरान उनके अड्डों व जहाजों को निशाना बनाएगा।

फ्रांस ने रिपोर्ट किया, “यह टकराव बीती रात की सीमित कार्रवाई पर समाप्त नहीं होगा। ईरानी हमले जारी रहेंगे और अक्रांतताओं के लिए यह काफ़ी दुखदायी और पश्चातापजनक होगा”।

अधिकारियों ने कहा कि यह युद्ध आने वाले दिनों में इस (इज़राइली) शासन द्वारा क़ब्ज़ा किए गए सभी क्षेत्रों और क्षेत्र में मौजूद

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित

केन्द्र सरकार ने इस 11 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की जो तीन माह में रिपोर्ट देगी

नयी दिल्ली, 14 जून। सरकार ने है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने पिता को अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर एक दुर्घटना में खोया है। उन्होंने कहा इंडिया के विमान की गुरुवार को दुर्घटना की समग्रता से जांच के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इस दुर्घटना को लेकर हर तरह के सवाल का जवाब तलाशेगी और तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने शनिवार को यहां उड़ान भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी और यह भी बताया कि विमान का डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया और उसकी डिकोडिंग का जा रही है। नायडू ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि वे इस दुर्घटना के शिकार यात्रियों के परिजनों के दर्द को समझते

राहुल गांधी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिक बेरोजगार युवाओं को नियुक्त पत्र सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवाओं में बढ़ ती और नए को लत मानसिक अवसाद को देखते हुये उन्हें इससे मुक्ति दिलाने के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट, एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, महिन्द्रा, एमेज़ॉन, जेप्टो, टाटा, सीमेरग, हीरो, बजाज, वोल्टास, जेड डायल, वोडाफोन, ब्लिंकिट और रेडिसन जैसी प्रमुख कंपनियां उन लगभग 100 कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने बेरोजगारों की सीधी भर्ती के लिए मैग जांब फेयर में भाग लेने पर सहमत जतायी है।

सीज़फायर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तबादला जैसलमेर किया था। अपील में कहा गया कि अब दोनों देशों के बीच सीज़फायर हो गया है और तनाव के हालात समाप्त हो गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने आपदा प्रबंधन के तहत अपने कर्मचारियों के किए गए ट्रांसफर वापस ले लिए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता का तबादला निरस्त कर उसे उसके गृह जिले में नियुक्त किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग को पूर्व में किए तबादला- आदेश पर नए सिरे से विचार करने को कहा है।

भारत को ऑयल बॉण्ड, ऑयल पर लगी एक्साइज इयूटी में कटौती आदि, सख्त कदम उठाने होंगे।

पर, कितनी महंगाई बढ़ती है, आदि, आदि, इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान-इज़रायल युद्ध कितने दिन चलता है। पर, कटु सत्य है कि भारत का “ग्रोथ मोमेंटम” तो पूर्णतया रूक जायेगा।

की कीमतों में तेज़ वृद्धि को रोकने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती पर विचार करना पड़ सकता है, जिससे उसकी आर्थिक गणना पर असर पड़ेगा। कमजोर होता रुपया डॉलर में तेल को हिस्सा है, लेकिन ये तात्कालिक संकट का समाधान नहीं दे सकती।

अब अगर क्या होगा, यह संघर्ष की दिशा पर निर्भर करता है। यदि शत्रुता सीमित रहती है और इसका असर जहाजों के परिवहन या तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं पड़ता तो कच्चे तेल की कीमतें 75 से 80 डॉलर प्रति बैरल के बीच स्थिर हो सकती हैं, जो कष्टकारी तो है लेकिन इससे डील किया जा सकता है। मध्यम स्तर के बढ़ते संघर्ष के तहत,

अमेरिकी अड्डों तक फैल जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने ईरान के इज़राइल पर हमलों को रोकने में मदद की, तो उनके अड्डों और जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा।

इज़राइल में हवाई हमले के सायरन पूरे देश में, विशेष रूप से तेल अवीव और यरुशलम में बजे, जिससे नागरिकों को बंकरों की ओर भागना पड़ा, क्योंकि ईरानी मिसाइलों की लगातार बारिश हुई और इज़राइली अवरोधक उन्हें रोकने के लिए सक्रिय हो गए।

इज़राइल की एम्बुलेंस सेवा के अनुसार, एक पुरुष और एक महिला की उस समय मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जब एक मिसाइल उनके घर के पास गिरी।

तेल अवीव के बाहर के शहर ऋशोन लेज़िओन में ध्वस्त हुए अपार्टमेंट भवनों के मलबे में बचाव दल तलाशी अभियान चला रहे हैं।

फिलिस्तीनी रेड क्रैसैंट के अनुसार, ईरान समर्थित हूती मिलिशिया द्वारा यमन से दागी गई एक मिसाइल ने इज़राइल-

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरानी ने कहा कि इज़राइली हमलों में 78 लोग मारे गए, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं, और 320 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें अधिकांश नागरिक हैं।

दो अमेरिकन अधिकारियों ने बताया, अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को इज़राइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। इज़राइल की सेना ने कहा कि ईरान ने शुक्रवार को 100 से कम मिसाइलें दागीं, जिनमें से अधिकांश को रोक लिया गया या वे लक्ष्य से चूक गईं।

दिनभर चले इज़राइली हमलों और उसके जवाब में हुई ईरानी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ा दी है, हालाँकि ईरान के सहयोगी शाज़ा में हम़ास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह पहले ही इज़राइल के हमलों में कमजोर हो चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख

राफेल ग्रोसी ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि तत्काल का पायलट परिशोधन केंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि फ़ोर्दों और इस्फ़ाहान में दो अन्य ठिकानों पर हुए इज़राइली हमलों की जानकारी अब भी एकत्र की जा रही है।

आरोपी पति को भारत डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की गई

जयपुर, 14 जून। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, महागिराव द्वितीय ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने से जुड़े मामले में पासपोर्ट कार्यालय से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पीठासीन अधिकारी कंचन सिंह राजावन ने पासपोर्ट अधिकारी से 4 अगस्त तक यह रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि उन्होंने एक अक्टूबर 2024 के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की और आरोपी को भारत डिपोर्ट कराने के लिए क्या प्रयास किए। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना में आरोपी का पासपोर्ट और वीजा निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पत्नी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

पीठासीन अधिकारी ने पासपोर्ट अधिकारी को 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा।

पत्नी के अधिवक्ता वाईके गुप्ता ने बताया कि अदालत ने रात एक अक्टूबर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासपोर्ट, जयपुर को निर्देश दिया था कि वे सेन्ट्रल अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए आरोपी पति को कोर्ट में पेशी का निर्देश दें। यदि वह स्वयं के खर्च पर एक महीने में पेश नहीं हो तो उसके पासपोर्ट-वीजा निरस्त कर उसे भारत डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालती आदेश के करीब सात माह बीतने के बावजूद, अब तक आदेश की पालना नहीं की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। गौतलब है कि पत्नी ने पति के खिलाफ मई 2024 में पुलिस थाना महिला-108 में दहेज प्रताड़ना व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जिसमें बुनियादी ढांचे पर अप्रत्यक्ष हमले या क्षेत्रीय टैकों को खतरे शामिल हों तो तेल की कीमतें 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। सबसे खराब स्थिति में, यदि होरमुज जलडमरूमध्य में पूरी तरह से नाकेबंदी या हमला होता है, कीमतें 120 डॉलर के पार जा सकती हैं, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में, महंगाई नाटकীয় रूप से बढ़ेगी, रुपया गिरावट का सामना करेगा, और तेल केंद्र सरकार को प्रतिक्रियात्मक उपायों के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तेल बॉन्ड, उत्पाद शुल्क कटौती, और आयात विधिवीकरण जैसी नीतिगत कुशलिंग कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन मूल समस्या बनी रहती है कि भारत की आर्थिक मशीनरी अब भी अस्थिर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार गिरफ्त में है, जहाँ भारी उतार-चढ़ाव है।

इज़राइल-ईरान संघर्ष ने भले ही भारत के हिੱतों को सीधे निशाना नहीं बनाया हो, लेकिन इसके आर्थिक झटके पहले से ही महसूस किया जा रहे हैं। जब

तक वैश्विक कूटनीति आगे बढ़कर तनाव को नियंत्रित नहीं करती, भारत का एक बार फिर बाहरी तेल संकट से जुझना पड़ सकता है, जो भी ऐसे समय में खराब अपनी वृद्धि की गति को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा की लड़ाई अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई बल्कि यह वास्तविक समय में घट रही है।

नाबालिग का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर बुलाया था और फिर वह उसे ट्रेन में बैठाकर अहमदाबाद ले गया। जहां उसे एक कमरे में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं, बाद में पुलिस और उसके परिजन आकर उसे ले आये। दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसके और पीड़ित पक्ष के बीच रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद था। ऐसे में द्वेषता के चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया।